the States. However, according to available estimates, the production of foodgrains during 1993-94 is likely to fall short of the target.

(b) The production of total foodgrains during 1993-94 at 182.04 million tonnes is likely to be higher by about 2 million tonnes or 1.1 per cent over the previous year as against the decline observed in the quarterly review of Indian economy of the NCAER.

(c) The States where shortfall in foodgrain production is likely to occur with respect to target include Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Rajasthan and Uttar Pradesh.

(d) It is too early to indicate the production of Kharif foodgrains during the current year. However, taking into consideration the rainfall and weather situation so far, it is expected that Kharif production during current year may be higher than the previous year.

(e) Production of rabi foodgrains during 1993-94 is presently estimated as 82.82 million tonnes.

(f) In order to increase the foodgrain production, the Government is implementing various crop oriented programmes including distribution of mini kits for improved seeds, subsidy on identified farm equipments, distribution of certified seeds, organisation of demonstration and training of farmers for transfer of technology, expansion of irrigation facilities, besides providing price and market support etc.

बाढ़ से कृषि योग्य भूमि की हुई क्षति और उससे हुई मौतें

1553. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष 18 जुलाई, 1994 तक बाढ़ बादलों के फटने से कितने लोग मारे गए कितनी कृषि-योग्य भूमि नष्ट हो गई तथा इसके परिणामस्वरूप कुल कितने रुपयों की हानि होने का अनुमान है ;

(ख) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने इस प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए भारत सरकार से कोई अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग की है, यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त आरंभिक रिपोर्टों के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून 1994 के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ से 18 जुलाई, 1994 तक विभिन्न राज्यों में 324 जानें गई तथा 2.27 लाख हैक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ । बाढ़ का जल स्तर कम हो जाने पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बाढ़ से हुई हानि का निर्धारण वित्तीय स्तरों पर किया जाता है ।

(ख) और (ग) बाढ़ राहत उपायों के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता तथा 1994-95 के दौरान दी गई आपदा राहत निधि के केन्द्रीय हिस्से का विवरण निम्न प्रकार है :

राज्य	मांगी गई सहायता (करोड़ रुपए में)	आपदा राहत निधि से निर्मुक्त केन्द्रीय हिस्सा (करोड़ रुपए में)
अरुणाचल प्रदेश	74.00	0.75
गुजरात	100.00	63.75
कर्नाटक	100.00	5.06
केरल	100.00	17.43
मध्य प्रदेश	200.00	20.81
उड़ीसा	188.41	14.89